ड्रोन निगरानी और पुलिस के कड़े पहरे के बीच 5 धार्मिक स्थलों समेत 12 अतिक्रमण जमींदोज

मालवीय नगर में नंदपुरी अंडरपास के पास रेलवे लाइन के समानांतर बनी 80 फीट चौड़ी सड़क में बाधा थे यह निर्माण

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मालवीय नगर में 1 मस्जिद, 2 मंदिर, 1 सत्संग भवन व 1 मजार समेत कुल 12 अतिक्रमणों को जयपुर विकास प्राधिकरण ने जमींदोज कर दिया। करीब 3000 पुलिकर्मियों की कड़ी सुरक्षा और ड्रोन की निगरानी में यह कार्रवाई हुई। हालांकि कार्रवाई के दौरान विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं रही।

ज्ञात रहे कि मालवीय नगर में नंदपुरी अंडरपास के पास रेलवे लाइन के समानांतर 80 फीट चौड़ी सड़क हैं, परंतु यहां अवैध अतिक्रमणों के चलते आम रास्ता 30-35 फीट का ही रह गया था। पिछले दिनों जेडीए ने यहां 134 से ज्यादा अतिक्रमणों को हटाते हुए धार्मिक स्थलों को स्वयं हटाने के लिए नोटिस दिए थे। खास बात यह रही कि जेडीए की कार्रवाई बिना किसी विरोध के शांति-पूर्ण संपन्न हो गयी। अब मौके से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।

- ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान चप्पे-चप्पे पर तैनात रहे पुलिसकर्मी, बैरिकेड्स लगाकर लोगों की आवाजाही रोकी
- इंटरनेट बंद के साथ सोशल मीडिया पर पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी

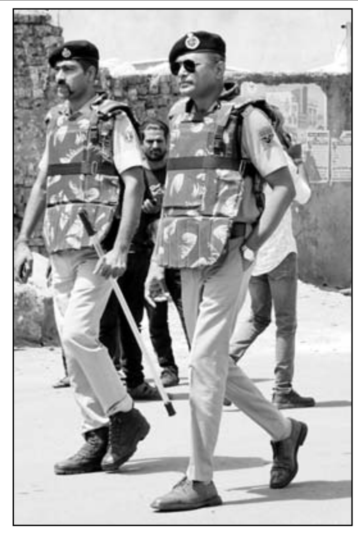

मालवीय नगर इलाके में सोमवार को जेडीए की टीम ने आम सड़क पर बनी मस्जिद, मजार, मंदिर व सत्संग भवन को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस का भारी जाप्ता तैनात रहा। पुलिस ने इलाके में बैरिकेड्स लगाकर आवाजाही रोक रखी थी, ऐसे में लोगों ने अपनी बालकनी खिड़की से तोड़फोड़ को देखा। फोटो-राष्ट्रदूत

उधर जेडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान पूरा मालवीय नगर क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील रहा। एहतियात के तौर पर पूरे जयपुर में इंटरनेट बंद रखा गया और नंदपुरी क्षेत्र में विद्युत स्प्लाई भी रोकी गई। चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती के साथ ही बैरिकेड्स लगाकर आमजन की आवाजाही बंद कर दी थी। पुलिस ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी, ताकि कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर पाए। रविवार रात 12 बजे से बंद किया गया इंटरनेट भी 19 घंटे के बाद सोमवार शाम को बहाल कर दी गई।

12 अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक 80 फीट सेक्टर रोड को चौड़ा करने के लिए जेडीए ने अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था सोमवार की कार्रवाई में 12 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही और किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया। स्थानीय लोगों ने भी शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया।

नॉर्थ इंडिया की इकलौती 'लोखंडा' मशीन मंगवाई

कार्रवाई के दौरान विशेष रूप से लोखंडा मशीन भी मंगवाई गई थी. बताया जा रहा है कि ये नॉर्थ इंडिया की एकमात्र लोखंडा मशीन है, जिसे विशेष तौर पर इस अभियान के लिए जयपुर मंगवाया गया था। भारी-भरकम लोहे के ढांचों, स्टील स्ट्रक्चर और मजबूत अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के लिए ये मशीन बैकअप के तौर पर तैयार रखी गई थी। हालांकि मौके पर मौजूद छोटी ध्वस्तीकरण मशीनों से ही निर्माण हटाने का काम पूरा हो गया, जिसके चलते लोखंडा मशीन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हाल ही में दिल्ली में एक होटल के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई में इसी मशीन का इस्तेमाल किया गया था।

मालवीय नगर का पूरा इलाका हाई अलर्ट पर

कार्रवाई को देखते हुए क्षेत्र में हजारों पुलिसकर्मी और आरएसी के जवान तैनात किए गए। कई ऊंची आवासीय इमारतों पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया, ताकि लोग छतों पर एकत्रित न हो सके। लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार लोगों से शांति बनाए रखने और भीड़ नहीं लगाने की अपील की जाती रही। मीडिया कर्मियों को भी निर्धारित सीमा से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरे अभियान की निगरानी करते रहे।

जेसीबी और डंपर से हटाया मलबा

ज्ञात रहे कि वर्तमान में करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी ये सड़क कई स्थानों पर केवल 25 से 30 फीट चौड़ी थी, जबकि रिकॉर्ड में इसकी चौड़ाई 80 फीट दर्ज है। ये मार्ग नंदपुरी अंडरपास को जगतपुरा से जोड़ता है और आसपास की कई कॉलोनियों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है।

नंदपुरी रोड की चौडाईकरण को लेकर हुई कार्रवाई जयपुर के हाल के सबसे "संवेदनशील अतिक्रमण हटाओ" अभियानों में गिनी जा रही है। प्रशासन जहां इसे शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में जरूरी कदम बता रहा है, वहीं पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई। आने वाले दिनों में सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य पूरा होने पर जगतपुरा और आसपास के क्षेत्रों को यातायात जाम से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

22 मई को हटाए थे 134 अतिक्रमण

उल्लेखनीय है कि जेडीए ने इसी मार्ग पर 22 मई को भी अभियान चलाकर 134 अतिक्रमण हटाए थे। इसके बाद शेष अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया था। प्रशासन ने क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर रखी है, जिसके तहत 22 जून तक बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन, रैली और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। इंटरनेट सुचारू होने के बाद भी सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी।

इंटरनेट बंद रखने से जनजीवन थमा, कारोबार प्रभावित हुआ

ऑनलाइन बुकिंग, डिजिटल भुगतान कैब और डिलीवरी सर्विस भी ठप

जयपुर। राजधानी जयपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद होने का असर सोमवार को आम जनजीवन और कारोबार पर साफ दिखाई दिया। ऑनलाइन भुगतान और इंटरनेट आधारित सेवाओं पर निर्भर लोगों को दिनभर परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां एक ओर दुकानदारों की बिक्री प्रभावित हुई, वहीं दूसरी ओर ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भर ऑटो चालकों और होम डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े राइडर्स का कामकाज लगभग ठप रहा।

ऑटो चालक प्रेम प्रकाश ने बताया कि सुबह से एक भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं मिली। इंटरनेट बंद होने से पूरा दिन खाली बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनकी अधिकांश आमदनी ऑनलाइन बुकिंग पर निर्भर है। ऑटो चालक दिलीप ने बताया कि वर्तमान में अधिकांश ऑटो चालक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। स्टैंड पर ऑफलाइन सवारी कम मिलने के कारण इंटरनेट बंदी का सीधा असर उनकी आय पर पड़ा है।

पूरे दिन एक भी ग्राहक नहीं मिलने से कमाई शून्य रही। छोले-कुलचे की रेहड़ी लगाने वाले अशोक, बाबूलाल और कमल ने बताया कि ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं। इंटरनेट सेवा बंद होने के कारण कई ग्राहक बिना

- ऑटो चालक, राइडर और दुकानदार भी परेशान हुए

खरीदारी किए लौट रहे हैं, जबकि कुछ लोग उधार में सामान लेकर बाद में भुगतान करने की बात कह रहे हैं। ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े राइडर हेमराज ने बताया कि इंटरनेट बंद होने से ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। सामान्य दिनों में वह प्रतिदिन एक हजार से पंद्रह सौ रुपए तक कमा लेते हैं, लेकिन सोमवार को एक भी डिलीवरी नहीं मिली। एक अन्य राइडर महेश ने बताया कि ऑनलाइन ऑर्डर बंद होने से कामकाज पूरी तरह ठप हो गया है। रोजाना की कमाई से ही घर का खर्च चलता है, लेकिन इंटरनेट बंदी के कारण आय प्रभावित हो गई है। शहर के विभिन्न बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी इंटरनेट बंदी का असर देखने को मिला। सामान्य दिनों में जहां बाजारों, बैंकों और कॉर्पोरेट कार्यालयों के आसपास चहल-पहल रहती है, वहीं सोमवार को कई डेयरी बूथ, चाय की थड़ियां और छोटी दुकानें बंद रहीं। कई दुकानदारों ने इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण दुकानें नहीं खोलीं।

इंटरनेट सेवाएं पुनः बहाल

जयपुर। जयपुर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति सामान्य होने के बाद प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं पुनः बहाल कर दी हैं। संभागीय आयुक्त वी. सरवण कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस आयुक्तालय जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध बनाए रखने की आवश्यकता नहीं बताई गई, जिसके बाद पूर्व में जारी अस्थायी निलंबन आदेश में संशोधन कर सेवाएं तत्काल प्रभाव से शुरू करने के निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था। इसके तहत मोबाइल इंटरनेट के साथ-साथ बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर) को 8 जून की मध्यरात्रि से 9 जून की मध्यरात्रि तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे।

भूमि विकास बैंकों के पुनरुत्थान की मांग उठाई सहकार नेता आमेरा ने

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक रवि बाबू को ज्ञापन सौंपा

जयपुर । ऑल राजस्थान कॉ-आपरेटिव बैंक एम्पलाईज यूनियन एवं ऑल राजस्थान को-ऑपरेटिव बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव एवं सहकारी साख समितियां एम्पलाईज यूनियन राजस्थान के प्रांतीय अध्यक्ष सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा ने मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास एवं मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड रविबाबू को ज्ञापन सौंपा। आमेरा ने अपने इस पत्र में राजस्थान प्रदेश में सहकारी भूमि विकास बैंकों का आर्थिक पुनरुत्थान एवं सुदृढीकरण कर किसानों के हित में भूमि विकास बैंकों के अस्तित्व को बनाये रखने की मांग की है। आमेरा ने पत्र में भूमि विकास बैंकों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में विलय करने के विचार को सिरे से खारिज करते हुए किसी भी प्रकार के विलय का विरोध जताया है। राज्य सहकारी विकास समिति की 21 मई को आयोजित बैठक में मुख्य सचिव द्वारा नाबार्ड से सहकारी भूमि विकास बैंकों की व्यवहार्यता का परीक्षण कर पुररुत्थान अथवा विलय के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है।

सहकार नेता आमेरा ने बताया कि प्रदेश में करोड़ों किसानों को दीर्घकालीन सहकारी ऋण सुविधा के लिए भूमि विकास बैंकों की व्यवहार्यता की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहल पर भूमि विकास बैंकों को मजबूती देने के लिए पहली बार राज्य सरकार द्वारा 200 करोड का बजट प्रावधान किया जाकर अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना लागू की गई, जिससे इन बैंकों द्वारा 337 करोड की वसूली की गई है। केन्द्र में पहली बार सहकारिता मंत्रालय, के गठन के साथ सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा देश के सहकारी भूमि विकास बैंकों के आर्थिक पुनरुत्थान, सुदृढीकरण एवं सक्षमता के लिए 225 करोड रुपये की कम्प्यूटराईजेशन ऑफ एआरडीबी परियोजना लागू की गई है। प्रदेश में भूमि विकास बैंकों के द्वारा सतत प्रयास कर गत वर्षो की तुलना में 175 करोड का ऋण वितरण कर एसएलडीबी वर्ष 2025-26 में 41 करोड़ के वार्षिक लाभ कमाया है तथा 36 पीएलडीबी में से 23 पीएलडीबी परिचालन लाभ में आ गई है। जबकि मुख्य सचिव द्वारा नाबार्ड से राजस्थान में भूमि विकास बैंकों को रखने या नहीं रखने की रिपोर्ट मांगी जा रही है। आमेरा ने मुख्य सचिव एवं मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड को यूनियन की तरफ से पत्र लिखकर प्रदेश के राज्य भूमि विकास बैंक एवं 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए कार्ययोजना लागू करने की मांग की है। भूमि विकास बैंकों को केंद्रीय सहकारी बैंकों में विलय का विरोध किया है। उन्होने राज्य सरकार से भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणों की वसूली के लिए गिरवी रखी गई भूमि की सहकारी अधिनियम के अनुसार नीलामी-कुर्की पर लगाई गई रोक को हटाकर बैंकों को ऋण वसूली प्रक्रिया शुरु करने देने की भी मांग की।

लॉँचिंग से पहले नोवा 2 व नोवा 2 प्रो स्मार्टफोन का रिव्यू करेगी कंपनी

नई दिल्ली । भारतीय स्मार्टफोन उद्योग में अपनी तरह की पहली पहल करते हुए एआई प्लस स्मार्टफोन ने घोषणा की है कि वह अपने आगामी नोवा 2 नियो और नोवा2 प्रो स्मार्टफोन को बिक्री शुरू होने से पहले ही देशभर के रिव्यूअर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, पत्रकारों और टेक्नोलॉजी समुदाय के सदस्यों को उपलब्ध कराएगा, ताकि वे इन डिवाइसेज़ की खुलकर समीक्षा कर सकें और अपनी निष्पक्ष राय दे सकें। एआई प्लस स्मार्टफोन के सीईओ और एनएक्सटीक्वांटम शिफ्ट टेक्नोलॉजीस के संस्थापक माधव शेठ ने कहा, ऐसे समय में जब प्रोडक्ट लॉन्च के साथ अक्सर पहले से तय और नियंत्रित संदेश पेश किए जाते हैं, एआई प्लस एक अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें लॉन्च के दिन की मार्केटिंग से ज्यादा उपभोक्ताओं के हित को प्राथमिकता दी जाती है। हमें सिर्फ तारीफ नहीं चाहिए, बल्कि उपयोगकर्ताओं के हित में ईमानदार और निष्पक्ष फीडबैक चाहिए। उन्होंने कहा कि नोवा2 नियो और नोवा2 प्रो को तब तक बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, जब तक यह फीडबैक अवधि पूरी नहीं हो जाती। उपकरण मिलने के 7 दिनों के भीतर समीक्षक अपने विचार पूरी स्वतंत्रता के साथ प्रकाशित कर सकेंगे। चाहे प्रतिक्रिया सकारात्मक हो, आलोचनात्मक हो या दोनों के बीच की कोई भी राय हो, ब्रांड उसे पारदर्शिता और लगातार सुधार की नजर से देखेगा।

बिजली विभाग एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करेगा : नागर

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । प्रदेश के विद्युत निगमों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कार्यकुशल बनाने के लिए एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) प्रणाली लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इसके लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री सोमवार को विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगमों तथा ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज निगम लिमिटेड से जुड़े सूचना प्रौद्योगिकी विषयों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज निगम लिमिटेड इस दिशा में सभी आवश्यक संभावनाओं पर कार्य करे, ताकि प्रदेश के सभी बिजली निगम एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित हो सकें। नागर ने कहा कि एकीकृत डिजिटल टूल विकसित होने से निर्णय प्रक्रिया अधिक त्वरित और सुगम बनेगी। मानव संसाधन, वित्त, लेखा, खरीद और परिसंपत्ति प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने से कार्य निष्पादन में दक्षता आएगी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली से उपभोक्ता सेवाओं में भी

- 'बिलिंग, शिकायत निवारण और विभिन्न सेवाओं की ट्रैकिंग अधिक प्रभावी तरीके से होगी'

सुधार होगा। बिलिंग, शिकायत निवारण और विभिन्न सेवाओं की ट्रैकिंग अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी, जिससे उपभोक्ताओं को त्वरित सेवाएं उपलब्ध होंगी। बैठक में शासन सचिव ऊर्जा एवं चेयरमैन डिस्कॉम्स आरती डोगरा ने बताया कि प्रदेश के वितरण निगम वर्तमान में 1.95 करोड़ से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 'बिजली मित्र' एप और वेब पोर्टल के माध्यम से नए कनेक्शन, बिजली बिल भुगतान, टैरिफ संबंधी जानकारी, शिकायत निवारण तथा आवेदनों की ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि एकीकृत बिजली प्रबंध मैनेजमेंट पोर्टल और एप के जरिए साइट सत्यापन, लागत अनुमान तैयार करना, विजिलेंस, पीडीसी सत्यापन, मीटर परीक्षण तथा ग्रिड सब-स्टेशन मॉनिटरिंग जैसे कार्यों में भी पारदर्शिता और सुगमता आई है।

सार-समाचार

बच्चियों को सिखाएं आत्मरक्षा के गुर

जयपुर । श्री माहेश्वरी महिला परिषद् जयपुर की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में नगर निगम की निवर्तमान चेयरमैन डॉ. मीनाक्षी शर्मा ने बच्चियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चियों को आत्मरक्षा के लिए किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा के लिए स्वयं मजबूत बनने की आवश्यकता है।

मानसून से पहले की तैयारियों पर चर्चा

जयपुर । कलेक्टर संदेश नायक ने सोमवार को मानसून की तैयारियों, शहर में नाला व सीवरेज लाइनों सफाई को लेकर बैठक ली। उन्होंने जीर्ण-शीर्ण विद्यालयों, आंगनबाड़ी केन्द्रों व पुराने निजी भवन चिन्हित करने के निर्देश दिए, ताकि बारिश के दौरान किसी अनहोनी से बचा जा सके। कलेक्टर ने बाढ़ नियंत्रण कक्षों की स्थापना के साथ ही आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश सभी उपखण्ड अधिकारियों व जिलास्तरीय अधिकारियों को दिए। नगर निगम प्रशासन को जयपुर शहर के सीवर लाईन एवं छोटे-बड़े गन्दे नालों की तत्काल सफाई करवाकर संबंधित अधिशाषी एवं सहायक अभियंताओं से प्रमाणीकरण कराने के निर्देश दिए। कलक्टर ने जिले के जलभराव क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर आवश्यकतानुसार फोगिंग एवं एंटी लार्वा एक्टीविटी के लिए कहा। विद्युत विभाग के अधिकारियों को मानसून से पूर्व ढीले तारों को कसवाने, जमीन पर रखे गए ट्रांसफार्मरों को उपर रखवाकर उसके चारों ओर अवरोधक लगवाने के निर्देश भी प्रदान किए हैं। नागरिक सुरक्षा उपनियंत्रक को "बाढ़ बचाओ" टीम में आवश्यकता अनुसार दक्ष प्रशिक्षित तैराक, गोताखोर, रेस्क्यूअर स्वयंसेवकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपखण्ड स्तर पर भी सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कर्मचारियों की अनदेखी पर फूटा गुस्सा

जयपुर । राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) की सुविधा बहाल करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने सहित पच्चीस सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत राज्य कर्मचारियों ने सोमवार से प्रदेशव्यापी जागृति यात्रा की शुरुआत कर दी। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में यह यात्रा जयपुर स्थित गवर्नमेंट हॉस्टल से रवाना हुई। यात्रा को कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान यात्रा में शामिल कर्मचारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जयपुर से रवाना हुई यात्रा बस्सी और कानोता होते हुए दौसा पहुंची, जहां स्थानीय कर्मचारियों ने यात्रा का स्वागत किया। महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य प्रदेशभर के कर्मचारियों को उनकी पच्चीस सूत्री मांगों के प्रति जागरूक करना और आगामी आंदोलन के लिए संगठित करना है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों ने पहले सांकेतिक प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर विरोध और सात दिन तक प्रतिदिन एक घंटे का कार्य बहिष्कार जैसे कार्यक्रम भी किए, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। इसके बाद कर्मचारियों ने प्रदेशव्यापी जागृति यात्रा निकालने का निर्णय लिया। महासंघ के अनुसार जागृति यात्रा 8 जून से 25 जून तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में पहुंचेगी। यात्रा के दौरान कर्मचारियों को उनकी मांगों और आगामी आंदोलन की रणनीति से अवगत कराया जाएगा।

घर के बाहर से वॉशिंग मशीन चोरी

जयपुर । मुहाना क्षेत्र में दिनदहाड़े चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। बाइक सवार दो बदमाश एक घर के बाहर रखी वॉशिंग मशीन को महज एक मिनट में चोरी कर फरार हो गए। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार चोरी की यह वारदात मुहाना मंडी स्थित केसर चौराहा निवासी भगवत सिंह राजावत के घर पर हुई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि बाइक पर सवार दो युवक पहले घर के आसपास रैकी करते हैं। इसके बाद दोनों घर के मुख्य गेट के बाहर रुकते हैं।

सरकारी कस्टडी से नकली खाद चुराने की कोशिश करने वाले दो गिरफ्तार

कृषि विभाग ने पिछले दिनों सील किया था गोदाम, आरोपियों ने ताला तोड़कर चोरी की कोशिश की

जयपुर (कासं)। हरमाड़ा पुलिस ने कृषि विभाग द्वारा सील किए गए एक गोदाम से सरकारी अभिरक्षा में रखी नकली खाद चोरी करने के प्रयास का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी कर ले जाई जा रही नकली खाद के 180 कट्टे, एक ट्रेलर और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बरामद खाद की अनुमानित बाजार कीमत करीब तीन लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में गोदाम मालिक और दो मुनीम फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

जयपुर पश्चिम के पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि दुर्गापुरा उद्यान कार्यालय के कृषि अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक सांवर मल यादव की ओर से हरमाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि कृषि विभाग की टीम ने 29 मई 2026 को सीकर रोड स्थित रामलियावाला में बिना नाम-पट्टिका के संचालित एक गोदाम पर छापा मारा था। जांच के दौरान वहां नमक, रंग और अन्य कच्चे माल से नकली डीएपी (डीएपी) और एमओपी (एमओपी) खाद तैयार कर उसे नामी कंपनियों के ब्रांडेड कट्टों में पैक कर बाजार में सप्लाई करने का खुलासा हुआ था।

- गोदाम मालिक व दो मुनीम फरार, दोनों की तलाश में जुटी पुलिस

कार्रवाई के दौरान कृषि विभाग ने मौके से नमूने लिए और गोदाम में रखे माल को सील एवं चपडी कर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए मौके पर मौजूद मुनीम नरेंद्र मीणा को सुपुर्द कर दिया था। पुलिस के अनुसार कृषि निरीक्षक सांवर मल यादव को सूचना मिली कि सील किए गए गोदाम का ताला तोड़कर भीतर से खाद निकाली जा रही है।

मौके पर पहुंचने पर गोदाम की सील टूटी हुई और शटर खुला मिला। जांच में सामने आया कि गोदाम मालिक निखिल शर्मा, मुनीम कमलेश मीणा और राजेश गुर्जर ने कानूनी कार्रवाई से बचने तथा जब्त माल को बेचकर लाभ कमाने की नीयत से साजिश रची थी। आरोपियों ने एक ट्रेलर किराए पर लेकर गोदाम के पीछे खड़ा किया और आरोपी सुनील भारद्वाज ने शटर का ताला तोड़ दिया। इसके बाद मजदूरों की मदद से जब्त नकली खाद को ट्रेलर में भरना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस और कृषि विभाग की भनक लगने पर आरोपी ट्रेलर और मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर फरार हो गए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हरमाड़ा थानाधिकारी उदय सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया।

इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में सुनील भारद्वाज (34) निवासी खोरा श्यामदास दौलतपुरा जयपुर और गिरधारी शर्मा (48) निवासी श्रीमाधोपुर जिला सीकर गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में गोदाम मालिक निखिल शर्मा, मुनीम कमलेश मीणा तथा राजेश गुर्जर फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि वे इस तरह की अन्य अवैध गतिविधियों या चोरी की वारदातों में शामिल है या नहीं।